



UNFCCC COP29- बाकू

प्रलिस के लयः

[जलवायु परवऱतन पर संयुक्त राषट्र फरेमवरक कनवेंशन](#), [नया सामूहकऱ परमाणतऱ लकष्य](#), [कारबन बाज़ार](#), [संयुक्त राषट्र](#), [राषट्रीय सतर पर नरऱधारतऱ ढोगदान](#), [वैश्वकऱ मीथेन परतजऱज़ा](#), [लीमा वरक परोगराम ऑन जेंडर](#), [खादय और कृषऱ संगठन](#), [ग्रऱन कलाइमेट फंड](#), [परयावरण के लयऱ जीवन शैली \(LiFE\)](#), [जलवायु के लयऱ मैग्रोव गठबंधन](#) ।

मेन्स के लयः

भारत की जलवायु नीतऱ, COP29 और ऱसके परणाम, वैश्वकऱ जलवायु शासन, वैश्वकऱ जलवायु पहल में भारत का नेतृत्व

[सुरतः ऱंडयऱन ँक्सप्रेस](#)

चरूा में कयों?

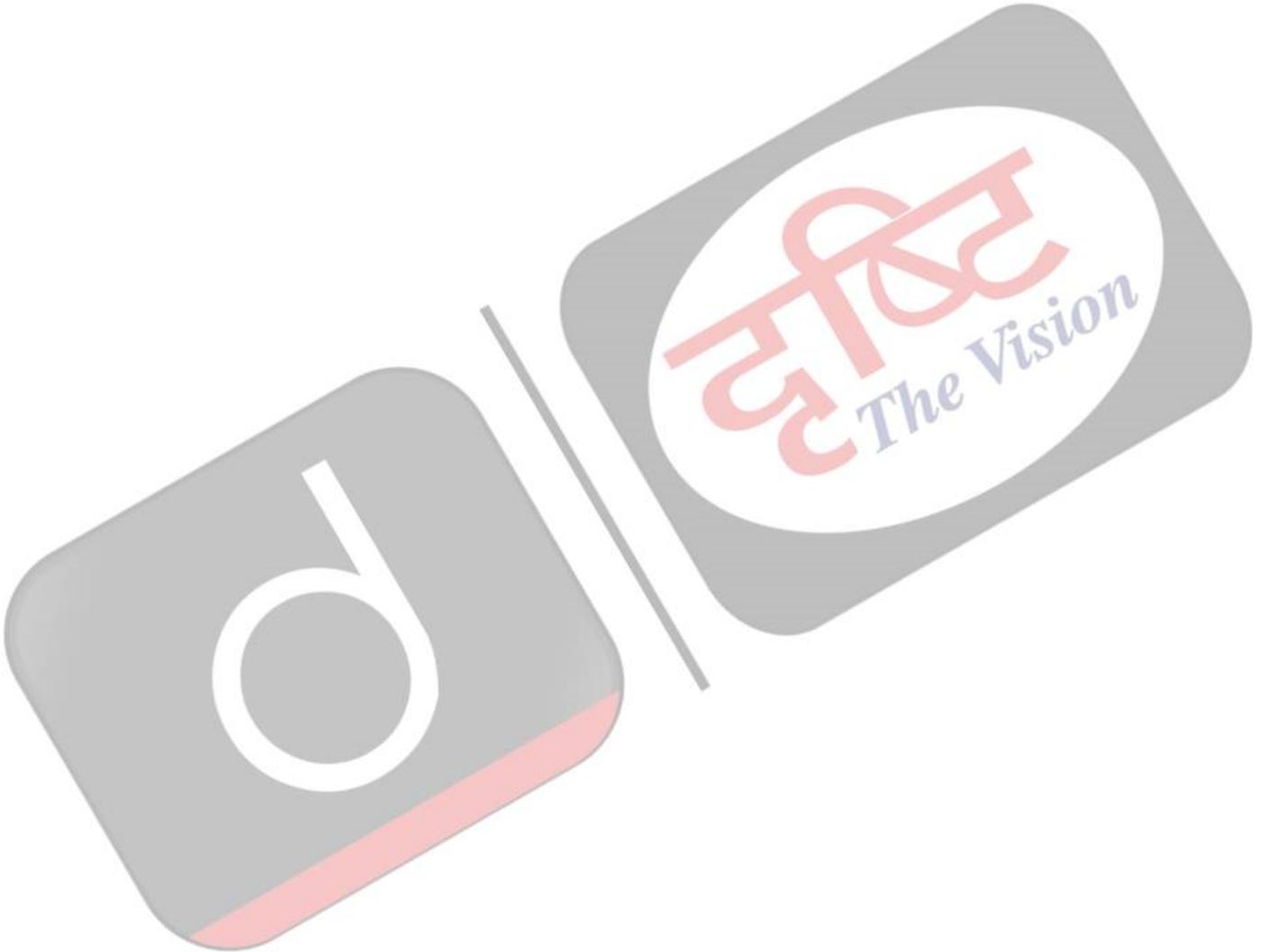
हाल ही में, [जलवायु परवऱतन पर संयुक्त राषट्र फरेमवरक कनवेंशन \(UNFCCC\) के पारटयऱों के 29वें सम्मेलन \(सीओपी29\) का समापन बाकू, अजरबैजान में हुआ](#) । ऱस सम्मेलन में लगभग 200 देशों के मध्य [वैश्वकऱ जलवायु चुनौतयऱों से](#) नपऱटने के उददेश्य संबन्धी समझौतों पर वारूा हुई ।

COP29 की मुखय बातें कया हैं?

- **नया जलवायु वतऱत लकष्य:** COP29 में ँक बड़ी सफलता [जलवायु वतऱत पर नया सामूहकऱ परमाणतऱ लकष्य \(NCQG\) है](#) । ऱसका उददेश्य वकऱसशील देशों के लयऱ जलवायु वतऱत को वरूष 2035 तक पूरूव लकष्य 100 अमेरकऱी डॉलर से बढ़ाकर 300 बलऱयऱन अमेरकऱी डॉलर परूतऱ वरूष तक अरूथात् तीन गुना कर वकऱसतऱ देशों को आगे रूखना है ।
 - ऱसमें सभी हतऱधारकों से वरूष 2035 तक समसूत सारूवजनकऱ और नज़ऱी सुरतों से जलवायु वतऱतपोषण को बढ़ाकर 1.3 टरूलऱयऱन अमेरकऱी डॉलर परूतऱ वरूष करने का आहूवान कयऱा गया है, ताकऱ वकऱसशील देशों को जलवायु परभावों को कम करने और उनसे अनुकूलन करने में सहायता मलऱ सके ।
- **कारबन बाज़ार समझौता:** COP29 ने [कारबन बाज़ारों](#) के लयऱ तंतरू को अंतमऱ रूप देने के लयऱ ँक ऐतऱहासकऱ समझौता कयऱा, जसऱमें [देश-दर-देश वयापार \(पेरसऱ समझौते का अनुच्छेद 6.2\)](#) और [संयुक्त राषट्र \(UN\) के तहत ँक केंद्रीकृत कारबन बाज़ार \(पेरसऱ समझौते का अनुच्छेद 6.4\)](#) शामिल है ।
 - अनुच्छेद 6.2, देशों के बीच पारसूपरकऱ रूप से सहमत शरूतों के आधार पर कारबन क्रेडऱट का वयापार करने के लयऱ दूवपऱकषीय समझौतों की अनुमता देता है ।
 - [पेरसऱ समझौता ःरण वयवसूथा](#) (जसऱ ँनुच्छेद 6.4 के नाम से भी जाना जाता है) का उददेश्य ँक केंद्रीकृत, [संयुक्त राषट्र](#) -परबंधतऱ [कारबन उत्सरूजन ऑफसेट और वयापार परणाली वकऱसतऱ करना है](#) ।
- **मीथेन कम करने पर ढोषणा:** अमेरकऱा, जरूमनी, बरूटऱन और संयुक्त अरब अमीरात समेत 30 से अधकऱ देशों ने [जैवकऱ अपशषऱट से मीथेन कम करने पर COP29 ढोषणा का समरूथन कयऱा \(भारत ऱसमें हसूताकषरकरूतता नहीं है\)](#) ।
 - ढोषणापतरू में [अपशषऱट कषेतरू के मीथेन उत्सरूजन को लकषतऱ कयऱा गया है](#), जो वैश्वकऱ मीथेन उत्सरूजन में 20% का ढोगदान देता है । यह पॉच पराथमकऱता वाले कषेतरूों पर धयऱन केंदरूतऱ करता है: [राषट्रीय सतर पर नरऱधारतऱ ढोगदान \(NDC\)](#), वनऱयऱमन, डेटा, वतऱत और भागीदारी ।
 - देशों को अपने NDC में [जैवकऱ अपशषऱट से मीथेन उत्सरूजन को कम करने के लयऱ कषेतरूीय लकष्य शामिल करने हेतु परूतऱसाहतऱ कयऱा जाता है](#) ।
 - यह [वैश्वकऱ मीथेन परूतजऱज़ा](#) (भारत ऱस पर हसूताकषरकरूतता नहीं है) पर आधारतऱ है, जसऱका लकष्य वरूष 2030 तक वैश्वकऱ मीथेन उत्सरूजन को 30% तक कम करना है, तथा कृषऱ, अपशषऱट ँवं [जीवाशम ऱंधन](#) से नषऱकासतऱ मीथेन की समसूथा का समाधान करना है ।
- **सूवदेशी लोग और सूथानीय समुदाय:** COP29 ने जलवायु परवऱतन से नपऱटने में [सूवदेशी लोगों और सूथानीय समुदायों](#) के महतूत्व पर ज़ोर दयऱा ।
 - COP29 ने बाकू कारूयऱोजना को अपनाया और [सूथानीय समुदाय और सूवदेशी लोगों के मंच \(LCIPP\)](#) के तहत [सुवधऱाजनक कारूय समूह \(FWG\)](#) के अधदऱश को नवीनीकृत कयऱा ।

- बाकू कार्ययोजना में स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने, **जलवायु संवादों में स्वदेशी भागीदारी को बढ़ाने** तथा जलवायु नीतियों में स्वदेशी मूल्यों को शामिल करने को प्राथमिकता दी गई है।
- **FWG बाकू कार्ययोजना** को लिंग-संवेदनशील और सहयोगात्मक तरीके से क्रियान्वति करेगा, जिसकी प्रगतिकी समीक्षा 2027 में की जाएगी।
- LCIPP का FWG एक **गठित नकिया है जिसकी स्थापना COP24** में LCIPP को और अधिक क्रियाशील बनाने तथा विविध नकियों के साथ कार्य करते हुए ज्ञान, सहभागिता और जलवायु नीतियों पर इसके कार्यों को सुगम बनाने के लिये की गई थी।
- **लिंग और जलवायु परिवर्तन: लैंगिक दृष्टिकोण पर लीमा वरक प्रोग्राम (LWPG)** को अगले 10 वर्षों के लिये बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे जलवायु कार्यवाही में लैंगिक समानता की पुष्टि हुई और **COP30 (बेलेम, ब्राज़ील) में एक नई लैंगिक कार्यवाही योजना को अपनाने** की आवश्यकता पर बल दिया गया।
 - 2014 में स्थापित LWPG का उद्देश्य लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देना तथा लैंगिक विचारों को एकीकृत करना है, ताकफ़िनर्वेशन और पेरसि समझौते के तहत लैंगिक-संवेदनशील जलवायु नीति और कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
- **किसानों के लिये बाकू हार्मोनिया जलवायु पहल: खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** के साथ साझेदारी में COP29 प्रेसीडेंसी ने किसानों के लिये बाकू हार्मोनिया जलवायु पहल शुरू की है।
- यह एक ऐसा मंच है जो खाद्य और कृषि के क्षेत्र में मौजूदा जलवायु पहलों के बखिरे हुए परदृश्य को एक साथ लाता है, ताककिसानों के लिये समर्थन प्राप्त करना आसान हो सके और वतित तक उनकी पहुँच सुगम हो सके।

//





UNFCCC काँफ्रेंस ऑफ पार्टिज (COP)

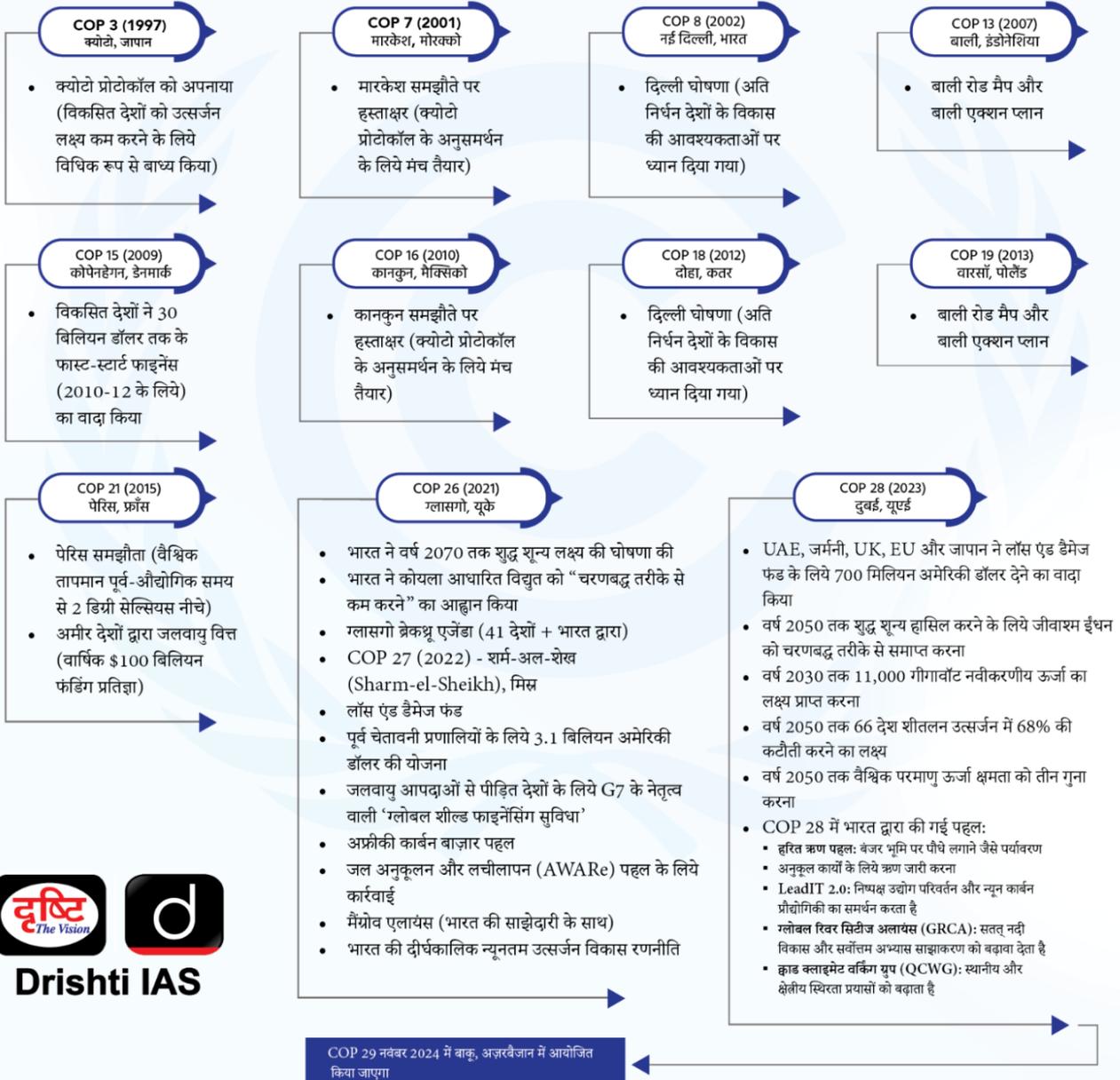


UNFCCC Conference of Parties (COP)

परिचय:

- UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय
- प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है (जब तक कि पक्ष अन्यथा निर्णय न लें)
- बॉन, सचिवालय में आयोजित होता है (जब तक कि कोई पक्ष सत्र की मेज़बानी करने की पेशकश न करे)
- पहला काँफ्रेंस ऑफ पार्टिज (COP) - बर्लिन, जर्मनी में आयोजित (1995) हुआ

COP और उनके परिणाम



COP 29 पर भारत का रुख क्या है?

- समझौते का वरिष्ठ: भारत ने NCQG की अपर्याप्तता की आलोचना करते हुए उसे **असवीकार** कर दिया। विकासशील देशों के सामने आने वाली

जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिये 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतबिद्धता को अपर्याप्त माना गया ।

- भारत, अन्य ग्लोबल साउथी देशों के साथ मलिकर, विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिये कम से कम **1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** प्रतविष की वकालत कर रहा है, जिसमें **600 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान या अनुदान-समतुल्य संसाधन** के रूप में शामिल हैं ।
- **पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9:** भारत ने इस बात पर जोर दिया कि **विकसित देशों को पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 के अनुरूप जलवायु वित्त जुटाने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये**, जिसमें विकसित देशों पर ज़िम्मेदारी डाली गई है ।
 - हालाँकि, अंतिम समझौते ने विकसित देशों को उनके **ऐतहासिक उत्सर्जन और वित्तीय प्रतबिद्धताओं** के लिये जवाबदेह ठहराने के बजाय, विकासशील देशों सहित **सभी पक्षों पर ज़िम्मेदारी डाल दी** ।
- **कमज़ोर राष्ट्रों के साथ एकजुटता:** भारत ने **अल्प विकसित देशों (LDC)** और **लघु द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS)** की चिंताओं का समर्थन किया, जिन्होंने यह कहते हुए वार्ता से कनिरा कर लिया कि उचित और पर्याप्त वित्तीय लक्ष्य की उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है ।

भारत के लिये COP क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **भारत की जलवायु प्रतबिद्धताएँ और उपलब्धियाँ:** भारत की पहली **NDC वर्ष 2015 में प्रस्तुत** की गई थी, और इसने वर्ष **2022 में अपने जलवायु लक्ष्यों** को अद्यतन किया, जिसमें **उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करने** और **गैर-जीवाश्म ईंधन से अपनी ऊर्जा कषमता का 40% पूरा करने** जैसी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया ।
- **जलवायु वित्त को सुरक्षित करना:** भारत **हरति जलवायु कोष** और कार्बन क्रेडिट बाज़ार जैसे तंत्रों के माध्यम से प्राप्त धन का प्रमुख लाभार्थी रहा है ।
 - भारत के लिये बाढ़ और चक्रवात जैसे **जलवायु-प्रेरित प्रभावों से** निपटने के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु **हानि और क्षति कोष** पर COP चर्चाएँ महत्त्वपूर्ण हैं ।
- **वैश्विक जलवायु नेतृत्व:** **COP भारत को वैश्विक जलवायु कार्रवाई** में अपने नेतृत्व का दावा करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें वैश्विक जलवायु चुनौती के लिये स्थायी समाधान को आगे बढ़ाने के क्रम में **अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** जैसी पहल शामिल हैं ।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रभाव का लाभ उठाना:** भारत COP में **समान वधिारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC)** और **BASIC समूह** का नेतृत्व करता है, जो **ग्लोबल साउथ** के प्रभाव को बढ़ाने के साथ **न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई एवं वित्तपोषण** में सहायक है ।
 - **COP जैसे मंच भारत को पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली (LiFE)** के साथ **जलवायु हेतु मैंग्रोव गठबंधन** जैसी पहलों को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं ।

वैश्विक जलवायु शासन में भारत की भूमिका कसि प्रकार विकसित हुई है?

- **1970 से 2000 का दशक:** इस दौरान भारत पश्चिमी पर्यावरणीय आहवानों के प्रतिसात्क था क्योंकि भारत को आशंका थी कि इससे उसके आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी ।
 - **वर्ष 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन** में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने **पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन** के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया था ।
 - **वर्ष 1992 के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शखिर सम्मेलन में UNFCCC** पर हस्ताक्षर करके भारत ने औपचारिक रूप से सतत् विकास को अपनाया तथा **साझा लेकनि वभिदति उत्तरदायित्वों (CBDR)** का समर्थन किया, जिसमें विकसित तथा विकासशील देशों की अलग-अलग कषमताओं एवं ज़िम्मेदारियों को मान्यता दी गई ।
 - भारत ने **वर्ष 2002 में COP8 की मेजबानी की थी**, जो जलवायु वार्ता में नषिकरयि भागीदारी से सकरयि भूमिका की ओर भारत के बदलाव का प्रतीक थी ।
 - भारत ने **वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC)** को अपनाया था, जो उत्सर्जन को कम करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रतारि भारत की प्रतबिद्धता का परिचायक है ।
- **वर्ष 2015 के बाद:** पेरिस समझौता, 2015 से वैश्विक जलवायु शासन में प्रमुख बदलाव आने के साथ भारत जैसे विकासशील देशों को असंगत दायित्वों का सामना कयि बिना **जलवायु कार्रवाई में योगदान** करने का प्रोत्साहन मला ।
 - कठोर उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों के क्रम में **राष्ट्रीय स्तर पर अभनिरिधारति योगदान (NDC)** की ओर परिवर्तन से भारत को अपनी जलवायु प्रतबिद्धताओं को विकासात्मक प्राथमकताओं के साथ संरेखति करने में सहायता मिलती है ।
 - भारत ने **राष्ट्रीय स्तर पर अभनिरिधारति योगदान (NDC) प्रस्तुत कयि** तथा वर्ष 2022 में उन्हें अद्यतन किया ।
 - भारत ने वर्ष 2022 में अन्य विकासशील देशों के लिये **जलवायु वित्तपोषण हेतु 1.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया**, जिससे **जलवायु नेतृत्वकर्त्ता** के रूप में इसकी भूमिका मज़बूत हुई ।
- **जलवायु समानता एवं न्याय के लिये वकालत:** भारत विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने की वकालत करने के साथ **हरति जलवायु कोष एवं लॉस एंड डैमेज फंड जैसी व्यवस्थाओं का सकरयि रूप से समर्थन करता है** ।
- **अग्रणी वैश्विक पहल:**
 - **अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 शखिर सम्मेलन में शुरू कयि गए **ISA** का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है ।
 - **पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली (LiFE):** इसके तहत **कार्बन फुटप्रटि** को कम करने के लिये धारणीय उपभोग पैटर्न की वकालत की गई है ।
 - **जलवायु हेतु मैंग्रोव गठबंधन:** यह जलवायु प्रभावों को कम करने के लिये मैंग्रोव पारस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रति है ।

प्रश्न: COP29 के परिणामों एवं वैश्विक जलवायु शासन हेतु उनके नहितार्थों पर चर्चा कीजिये। भारत का दृष्टिकोण जलवायु लक्ष्यों एवं विकास प्राथमिकताओं के साथ किस प्रकार संतुलित है?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/unfccc-cop29-baku>

